



बिहार सरकार

**बिहार महादलित विकास मिशन
(महादलितों के विकास हेतु किए जा रहे कार्य)**

1. विकास मित्र

सरकार के सभी योजनाओं को महादलितों के विकास हेतु प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत(ग्रामीण) एवं वार्ड/वार्ड समुह (शहरी) से बहुलता वाले महादलित समुदाय के एक-एक विकास मित्र का चयन किया जा रहा है। विकास मित्रों के चयन में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति के पंचायत से ही किया जाएगा, तथा किसी भी परिस्थिति में पंचायत के बाहर के आवेदक का चयन नहीं किया जाएगा। प्रतिमाह 3000/- रू० मानदेय निश्चित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से तीन चरणों में चयन किया गया है।

विकास मित्र सरकार एवं महादलित परिवारों के बीच एक कड़ी के रूप में एवं महादलित समुदाय में एक Change Agent के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास मित्र नियोजन से संबंधित प्रक्रिया के तीन चरणों के उपरांत 9875 रिक्तियों में 8930 विकास मित्रों का चयन कर लिया गया है 945 विकास मित्रों का चयन करना शेष है:-

चरणवार स्थिति:

चरण	आवेदन की तिथि	शैक्षणिक योग्यता	कुल नियोजन की संख्या	योगदान की तिथि	प्रशिक्षण
प्रथम चरण	22/02/2010	मैट्रिक या समकक्ष	6426	14/04/2010	2 राज्य स्तरीय 11 प्रमंडल स्तरीय
द्वितीय चरण	01/06/2010	पुरुष- मैट्रिक या समकक्ष महिला- आठवीं पास	1753	15/07/2010	
तृतीय चरण	14/07/2010	पुरुष- पाँचवीं तक महिला- साक्षर तक	751	01/09/2010	
कुल			8930		

रिक्तियों को भरने के लिए शीघ्र ही चतुर्थ चरण की शुरुआत की जायेगी ।

विकास मित्रों को साईकिल देने के लिए जिलों को कुल 163 लाख रूपए विमुक्त की गई है। साईकिल की राशि का वितरण शीघ्र कर लिया जाना है।

विकास मित्रों को मानदेय देने के लिए दिसम्बर 2010 तक के लिए 22.48 करोड़ रु० की राशि विमुक्त कर दी गई है। जिसमें अक्टूबर माह तक सभी जिलों में मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।

चतुर्थ चरण में रिक्त स्थानों पर नियोजन हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। दिनांक 20/12/2010 से 31/01/2011 तक नियोजन कार्य पुरा किया जायेगा।

2. मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना

वित्तीय वर्ष 2009-10 में सरकारी विद्यालयों के 1 से 5 वर्ग तक के सभी महादलित छात्र-छात्राओं को 500/- रु० पोशाक, जूता आदि क्रय करने हेतु नगद राशि उपलब्ध करायी गयी। यह कार्रवाई सभी जिलों में दिनांक 11 जुलाई 2009 को पंचायत स्तरीय शिविर लगाकर जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभार्थियों को राशि का भुगतान किया गया। सभी जिलों में वितरण समारोह का फोटोग्राफी/विडियोग्राफी भी किया गया। अब तक लगभग 842537 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो चुके हैं। कुल 44 करोड़ 8 लाख व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस योजना के अंतर्गत पहले और दूसरे वर्ग के छात्र-छात्राओं को आच्छादित किया जा रहा है जिसमें लगभग 38 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। तृतीय से पंचम वर्ग के छात्र-छात्राओं को मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आच्छादित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 36 करोड़ 90 लाख रुपये विमुक्त किए गये हैं जिसमें प्रथम किस्त के रूप में विभिन्न जिलों को 14 करोड़ 3 लाख रुपये एवं द्वितीय किस्त के रूप में 22 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गई है। कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 7 लाख 20 हजार होगी। 26 जनवरी 2011 तक पोशाक की राशि के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकतानुसार जिला से माँग के आधार पर शेष राशि विमुक्त की जाएगी।

3. दशरथ मांझी कौशल विकास योजना

महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पाँच प्रतिष्ठित संस्था/ गैर सरकारी संगठनों का चयन किया गया है।

व्यवसाय एवं प्रशिक्षण क्षेत्र का विवरण निम्नवत है:-

क्रम	कोर्स का नाम	अवधि	योग्यता	प्रस्तावित जिला	संस्था का नाम
1	कम्प्युटर प्रशिक्षण (डी0 टी0 पी0 एवं इंटरनेट)	3 माह	दसवीं पास	सभी जिला	ECIL
2	ईलेक्ट्रीकल वायरिंग	3 माह	आठवीं पास	पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर	ECIL
3	कम्प्युटर एकाउंटिंग (टैली)	4 माह	इंटरमिडिएट पास	सभी जिला	Tally
4	भवन निर्माण (ड्राफ्ट्समैन)	8 सप्ताह	इंटरमिडिएट पास	पटना एवं गया	IIIM Ltd.

5	भवन निर्माण (साईट सपोर्ट)	8 सप्ताह	आठवीं पास	पटना, गया, नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर, मधुबनी, नवादा	IIIM Ltd.
6	सिक्युरिटी गार्ड्स प्रशिक्षण	4 सप्ताह	आठवीं पास	पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर	IIIM Ltd
7	मोबाईल रिपेयरिंग	8 सप्ताह	इंटरमिडिएट पास	पटना	IIIM Ltd
8	ब्युटीसियन कोर्स	6 माह	आठवीं पास	पटना, गया, मुज़फ्फरपुर	DORD
9	हॉस्पिटलिटी एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	15 दिन	पांचवीं पास	पटना	NIDAN
कुल लक्षित संख्या - 13,530					

इस योजना की मुख्य विशेषताएँ

- 1- पूर्णतः निःशुल्क
- 2- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद नियोजन की व्यवस्था
- 3- प्रशिक्षण के दौरान मिशन के द्वारा स्टार्डपेंड (75 रुपये प्रति दिन के दर से पुरी प्रशिक्षण अवधि में)
- 4- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण पाठ्य-सामग्री/प्रशिक्षण टूल-क्रीट निःशुल्क
- 5- व्यक्तित्व विकास के लिए कोर्स मॉड्युल का समावेश
- 6- बेहतर कैरियर एवं उज्जवल भविष्य
- 7- आत्म-विश्वास का विकास

योजनान्तर्गत कुल 13530 युवक/युवतियों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रथम बैच में 3370 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दी जा चुकी है। सिक्युरिटी गार्ड्स प्रशिक्षण की सफलता को देखते हुए द्वितीय बैच के रूप में सिक्युरिटी गार्ड्स प्रशिक्षण को बिहार के सभी 38 जिलों में विस्तारित किया गया है। सिक्युरिटी गार्ड अरवल एवं मधेपुरा को छोड़ कर बिहार के सभी जिलों में प्रशिक्षण पुरी कर ली गयी है। द्वितीय बैच में 1155 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दी जा चुकी है।

शैक्षणिक योग्यता एवं आय के आधार पर की गई।

- कुल ट्रेड - 9
- कुल चयनित एजेंसी - 5
- कुल लक्षित संख्या - 13530
- कुल प्रशिक्षित - 4525
- कुल प्लेसमेंट - 1810
- छात्रवृत्ति वितरित - 2.10 करोड़
- कुल प्रशिक्षण व्यय - 5.30 करोड़

दशरथ माँझी कौशल विकास योजना के तहत दूसरा चरण शीघ्र आरंभ किया जाना है। दशरथ माँझी कौशल विकास योजना 2010-11 के लिए 23 विभिन्न ट्रेडों में अभिरूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। अभिरूचि 2010 तक थी। अभिरूचि प्रस्ताव संसाधित किये जा रहे हैं।

4. सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण

योजना अन्तर्गत महादलित टोला में सामुदायिक भवन का निर्माण महादलितों के समाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में किया जा रहा है। भवन का डिजाईन चबुतरा आधारित चारों तरफ पार्सिप वाला कॉलम एवं उपर शेड बना होगा। इस तरह की संरचना पर कम लागत आयेगी और अधिक संख्या में समुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा। इसके निर्माण में लगभग 4 लाख 50 हजार रुपया व्यय होगी। समुदायिक भवन सह- वर्कशेड का निर्माण जिला-पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से विकास मित्र (अभिकर्ता) के द्वारा करवाया जा रहा है।

समुदायिक भवन सह- वर्कशेड की मार्गदर्शिका विकसित की गयी है जिसमें विकास मित्र के माध्यम से निर्माण किया जायेगा।

अब तक 12 जिलों से जमीन उपलब्धता का प्रतिवेदन बिहार महादलित विकास मिशन को प्राप्त हुआ है।

500 रु० की राशि विमुक्त की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल 650 सामुदायिक भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। विभाग से राशि प्राप्त होते ही शीघ्र जिलों को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

30 करोड़ रु० वर्ष 2010-11 व्यय किया जायेगा।

5. सहायता (कॉल सेंटर)

'सहायता' बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा स्थापित पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉल सेंटर है। इस कॉल सेंटर की स्थापना मुख्य रूप से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के अन्तर्गत की गई है। 'सहायता' अनु० जाति एवं अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले शिकायतों को प्राप्त करेगा और उसका समुचित निराकरण करने में अभिवंचित वर्ग की सहायता करेगा। इस कार्य के अतिरिक्त 'सहायता' बिहार महादलित विकास मिशन एवं अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी मांगकर्ता तक पहुँचाएगी साथ ही मिशन एवं विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी लाभुकों, जो अभिवंचित वर्ग के सदस्य हैं, से प्राप्त कर समाधान के लिए संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रेषित करेगी।

'सहायता' कॉल सेंटर की तरह कार्य कर रहा है इस हेतु एक टॉल फ्री नं०-18003456345 बी०एस०एन०एल० से लिया गया है जिस पर एक साथ 30 कॉल आने जाने

की सुविधा है। वर्तमान में एक शिफ्ट में छः 'सहायता' प्रतिनिधि (कॉल एजेंट) के एक साथ कार्य करने की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान समय में सहायता 10 बजे से 5 बजे तक 3 ऑपरेटरों द्वारा इन्दिरा भवन, बिहार महादलित आयोग के कार्यालय में संचालित करवाया जा रहा है।

कुशल निष्पादन हेतु नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति।

Total- Call –	1576 (31/11/10 तक)
अत्याचार –	52
सूचना –	706
समस्या –	817

6. विशेष विद्यालय -सह- छात्रावास

दानापुर में (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) मुसहर बालिकाओं के लिए नारी-गुंजन गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से चलवाया जा रहा है। मुसहर बालिकाओं के छात्रावास के प्रस्ताव को विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास कार्यक्रम से आच्छादित किया गया है। बिहार में मुसहर महिलाओं में साक्षरता दर 0.9% होने के कारण विशेष बल के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। छात्रावास में विभिन्न कक्षाओं की 125 मुसहर साथ ही उन्हें कम्प्यूटर का भी पूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है। उपयोगिता के आधार पर चार किस्तों में 30 लाख 80 हजार रुपये उक्त संस्था को प्रदान की जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 11 लाख 41 हजार रुपये उक्त संस्था को प्रदान की गयी है।

कम्प्यूटर शिक्षा शुरू कर दी गई है।

7. महादलित शौचालय निर्माण योजना

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु महादलित परिवार (लाभार्थी) के सहांश (Contribution) 300/- रु० प्रति परिवार को बिहार महादलित विकास मिशन की ओर से देकर निःशुल्क शौचालय निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के तहत 7.00 करोड़ रु० की राशि मिशन के द्वारा जिला परियोजना पदाधिकारी सह जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराकर जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से कार्यावित किया जा रहा है। सभी जिले में योजना कार्यान्वित की जा रही है। अब तक

प्राप्त आंकड़ा के अनुसार 1,04,550 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करा दी गयी है जिसमें कुल 3 करोड़ 13 लाख रु० राशि व्यय किया गया है।

शहरी क्षेत्र में भी महादलित शौचालय निर्माण के लिए योजना तैयार की जा रही है। महादलित शहरी शौचालय निर्माण योजना के लिए अभिसूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसमें पचास एजेंसियों ने भाग लिया 6 एवं 8 जुलाई 2010 को प्रस्तुतिकरण दिया गया। एजेंसियों द्वारा शहरी शौचालय के संख्या का आकलन तदोपरांत निर्णय लिया जाएगा।

8. मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत महादलित महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित कर उनका आर्थिक मधुबनी एवं खगड़िया के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दशरथ माँड़ी कौशल विकास योजना में प्राथमिकता से चयन करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं ।

भोजपुर एवं वैशाली में रुरल बैकयार्ड पॉल्ट्री डेवलेपमेंट योजना (मुर्गी ग्राम योजना) का संचालन किया जा रहा है । इस योजना के तहत कुल 1 मिशन द्वारा योजना कार्यावयन हेतु पशुपालन विभाग को 215(दो सौ 2010) को किया गया । इस योजना के अंतर्गत 48 मदर यूनिट स्थापित हो चुके हैं । उपरोक्त छः जिलों में गया में 9360 एवं जहानाबाद में 12493 चुने मदर यूनिट में पहुंचाये जा चुके हैं ।

9. महादलित आवास भूमि योजना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा महादलित परिवारों का सर्वेक्षण करा कर भूमिहीन/ आवासहीन परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसे परिवारों को प्रति परिवार 3 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। 1,157 एकड़ गैर मजरूआ आम जमीन 41,293 परिवारों के बीच बंदोबस्त करने एवं 1,462 एकड़ गैर मजरूआ खास जमीन 49,378 परिवारों के बीच बन्दोबस्त करने की कार्रवाई किया जा रहा है। शेष बचे 1,11,428 महादलित परिवारों के लिए 9,040 एकड़ रैयती जमीन के क्रय कर उपलब्ध कराया जाएगा। रैयती जमीन क्रय के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 67 करोड़ रुपये बिहार के विभिन्न जिलों को आवंटित किये गये हैं । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस हेतु एक House site Scheme तैयार कर कार्यावित किया जा रहा है।

10. मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना

महादलितों को मुख्य धारा पर जोड़ने एवं प्रभावी जीवन दृष्टि बनाने हेतु इस योजना के तहत प्रत्येक महादलित परिवार को ट्रान्जिस्टर क्रय करने के लिए 400/- रु. दिया जाना है। पटना जिले के फुलवारीशरीफ प्रखंड के 739 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। इसे शीघ्र ही सभी जिलों में कार्यावित किया जाएगा

11. महादलित आंगनबाड़ी

महादलित बस्तियों में 500 परिवार पर कम-से-कम एक मिनि आंगनबाड़ी खोलने की योजना है। समेकित बाल-विकास सेवा (आई०सी०डी०एस) के माध्यम से कार्यावयन किया जाएगा । समेकित बाल-विकास सेवा (आई०सी०डी०एस) से प्रस्ताव प्राप्त होते ही 7 करोड़ तक की राशि विमुक्त कर दी जाएगी।

12. सामुदायिक रेडियो

महादलित वर्ग के कलाकारों को सम्मिलित कर रेडियो कार्यक्रम तैयार किया जायेगा एवं लोकगीत, लोककथाएं, लोकनृत्य आदि को प्रसारित किया जाएगा। अतः विभिन्न भाषायी केन्द्रों पर सामुदायिक रेडियो खोलने का प्रस्ताव है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर उनके लोकज्ञान को तो प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही

साथ सरकारी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाएगी। सामुदायिक रेडियो के लिए समाचार पत्रों में शीघ्र अभिसूचि अभिसूचि प्रस्ताव प्रकाशित की जाएगी।

मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि एवं सामुदायिक रेडियो योजना को प्रथम चरण में जोड़कर गया जिले के दो महादलित टोलों में स्थित सामुदायिक भवन में रेडियो लगाकर कार्यक्रम का आकलन किया जाएगा एवं तदोपरांत इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। विकास मित्र को इसके रखरखाव की जिम्मेवारी दी जाएगी 000 रुपये है। महादलित समुदाय से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम के लिए रेडियो प्रोग्राम निर्मित कर रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए अभिसूचि प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। अभिसूचि प्रस्ताव दाताओं की 2010 को किया गया। शीघ्र ही एजेन्सी का चयन कर योजना की शुरुआत किया जाएगा।

13. मैला प्रथा उन्मूलन

मैला प्रथा के उन्मूलन के लिए बिहार महादलित विकास मिशन के पदाधिकारियों द्वारा SRMS योजना के तहत मेगा कैम्प के सफल आयोजन हेतु राज्य के 38 जिलों में सघन अनुश्रवण कार्य किए गए। इस योजनांतर्गत कुल लाभवित 10000 व्यक्ति थे।

14. महादलित जलापूर्ति योजना

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु महादलित बस्तियों में 125 परिवार पर कम-से-कम एक स्वच्छ पेयजल का स्रोत उपलब्ध कराने के लिए मिशन द्वारा एक योजना की विस्तृत रूपरेखा बनाई गयी है। योजना का कार्यान्वयन मिशन के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग एवं सहभागिता से जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जायेगा।

15. महादलित आवास योजना

ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत महादलित परिवार को प्राथमिकता देकर लाभान्वित किया जा रहा है। भूमिहीन महादलित परिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त महादलित आवास योजना अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लाभान्वित किया जायेगा।

16. महादलित क्रेष

महादलित बस्तियों के आँगनबाड़ी के साथ एक-एक क्रेस खोलने का भी प्रस्ताव है। इसमें तीन वर्ष तक के बच्चों की देख रेख करने की व्यवस्था होगी। क्रेष खोलने से वे बच्चियाँ विद्यालय जा सकेंगी जिन्हें घर में बच्चों की देखभाल के लिए रूक जाना पड़ता है। इस योजना की शुरुआत पॉयलट स्तर पर शीघ्र की जायेगी तत्पश्चात समीक्षा के उपरान्त इसका विस्तार किया जायेगा।

17. धनवंतरी मोबाईल चिकित्सा योजना

महादलितों की बस्ती में स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए विशेष मोबाईल आयुर्वेदिक वैन चलाया जायेगा। योजना के कार्यावयन के संबंध में विचार-विमर्श कर एक कार्ययोजना का निर्माण किया गया है जिसके तहत राज्य को 10 जोन में बांट कर चिकित्सक, औषधि एवं जांच किट सहित वैन निश्चित स्थान एवं समय पर महादलित टोलों में उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

दस मेडिकल मोबाईल यूनिट शिघ्र ही बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा महादलितों के लिए प्रारंभ किये जा रहे रहे हैं जिसमें एक मोबाईल यूनिट प्रति प्रमंडल अवस्थित किये जाएंगे एवं शेष एक का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाएगा। मेडिकल मोबाईल यूनिट की खरीद करने के पश्चात उसकी साज सज्जा एवं सजावट का कार्य हो रहा है और शीघ्र ही अनुमंडल स्तर पर अवस्थित किया जाएगा।

18. महादलित स्वास्थ्य-कार्ड योजना

महादलित बस्ती में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड दिये जाने की योजना है। इस योजना का कार्यावयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड का प्रारूप राज्य के सभी सिविल सर्जनों को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रेषित कर दिये गये हैं जिसे शिघ्र ही छपवा कर महादलित परिवारों में वितरित किये जायेंगे।

19. अनुसूचित आवासीय विद्यालय

जिले के सभी अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली को लागू करा कर 60 प्रतिशत स्थान को महादलित समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त महादलित वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण संबंधी कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा, तथा इन आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं के पोषण स्तर का अध्ययन किया जाने वाला है।

20. महादलित बस्ती सम्पर्क योजना

महादलित बस्तियों को ग्रामीण पथ से जोड़ने के लिए एक महादलित बस्ती सम्पर्क पथ योजना तैयार की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। महादलित मिशन द्वारा इस योजना का अनुश्रवण किया जायेगा।

21. अन्य

आम आदमी बीमा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ महादलित समुदाय तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग से समन्वय किया गया है एवं विकास मित्र एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को इसके लिए संवेदित किया गया है। इस कार्य में प्रगति का निरंतर समन्वय किया जा रहा है।

मनरेगा का लाभ सभी महादलितों तक विकास मित्रों के माध्यम से अक्टूबर 2010 तक पहुँचाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के साथ समन्वय की जा रही है।